

मुख्यमंत्री 31 को करेंगे सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ

सरदार पटेल के नाम पर हर जिले में स्थापित होंगे औद्योगिक क्षेत्र

मनोज त्रिपाठी • जागरण

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग की तरफ से सभी जिलों में 100-100 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक व रोजगार क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। एमएसएमई विभाग ने पहले चरण के लिए फिलहाल 15 जिले चिह्नित किए हैं। इनमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, मीरजापुर, मऊ, बाराबंकी, जालौन, झांसी, कन्नौज, अलीगढ़, रायबरेली, इटावा, मेरठ, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर व भदोही शामिल हैं।

मुख्यमंत्री 31 अक्टूबर को 15 जिलों में योजना का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में 15 से 20 व तीसरे चरण में सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 90 लाख एमएसएमई इकाइयां संचालित की जा रही हैं। इनमें सूक्ष्म उद्योग की 89.64 लाख और लघु उद्योग की 36 हजार इकाइयां हैं। देश के एमएसएमई क्षेत्र में उग्र की हिस्सेदारी 14

100 एकड़ में की जाएगी स्थापना, इनमें रोजगार जोन भी होंगे

15 जिले एमएसएमई विभाग ने पहले चरण के लिए चिह्नित किए



पहली बार विभाग तैयार करेगा अपने औद्योगिक क्षेत्र

एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि विभाग वर्ष 1960 के बाद अब अपने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करेगा। अभी तक एमएसएमई विभाग के पास केवल भदोही में लैंड बैंक तैयार करने का अधिकार था, जिसे अब सभी

जिलों में विस्तारित किया जा रहा है। एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, स्ट्रीट लाइट, सुविधा केंद्र, सीईटीपी, प्रदर्शनी स्थल व उद्योग कार्यालय के साथ-साथ उद्योग व रोजगार से जुड़ी हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रतिशत है। एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से प्रदेश में 1.4 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत है। एमएसएमई के प्रमुख क्षेत्रों में वस्त्र एवं परिधान के अलावा हस्तशिल्प, हथकरघा, बुनाई, कढ़ाई, कालीन, चिकनकारी, चमड़ा, डेयरी, फल प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों के साथ-साथ आइटी सेवा, साफ्टवेयर विकास और डिजिटल मार्केटिंग में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी भागीदारी बढ़ाई है।

राज्य में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग लैंड बैंक तैयार कर रहा है। इसके लिए सभी जिलों में जिलाधिकारियों की मदद से भूमि चिह्नित की जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री के निर्देश पर 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र व रोजगार योजना के तहत निवेशकों को 1000, 2000 व 4000 वर्ग मीटर के भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष तौर पर रोजगार जोन की भी स्थापना की जाएगी।